2007

वित्त मंत्री श्री स्टीफेन मरांडी का बजट भाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय

1. राज्य का आय-व्ययक सदन में प्रस्तुत करने का यह मेरा पहला अवसर है। मैं वित्तीय वर्ष 2007-08 का आय-व्ययक प्रस्तुत करने के लिए आप सभी के बीच इस सदन में खड़ा हूँ। निःसंदेह मेरे लिए यह एक सुखद अनुभूति का अवसर है। इसके लिए मैं आपके प्रति, सदन के प्रति, अपने युवा मुख्य मंत्री श्री मधु कोड़ा के प्रति तथा झारखण्ड की जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

2. अध्यक्ष महोदय, झारखण्ड आन्दोलन में मैंने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया है। लाखों लोगों ने उस आन्दोलन को सफल बनाया जिसका परिणाम 15.11.2000 को देखने को मिला जब झारखण्ड अलग राज्य बना। उस आन्दोलन में काफी लोगों ने अपनी-अपनी तरह से कुर्बानियाँ दी है। मैं उन सभी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, अभार व्यक्त करता हूँ।

3. अध्यक्ष महोदय, जब झारखण्ड आन्दोलन चल रहा था तो हम सभी के मन में यह बात उठती थी कि, झारखण्ड में झारखण्ड वासियों का शासन होगा और वे अपने भाग्य का फैसला स्वयं कर सकेंगे। आज निःसंदेह हम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं। यहाँ झारखण्ड के लोगों का शासन है। इसलिए झारखण्डवासियों की अपेक्षाओं तथा आकांक्षाओं के अनुरूप विकास हो, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है।

4. हम सभी जानते हैं कि झारखण्ड राज्य की आबादी के लगभग 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं और ये सभी कृषि पर निर्भर हैं। यदि कृषि का समुचित विकास हो जाय तो झारखण्ड की एक बहुत बड़ी आबादी की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो सकती है। हमारी सरकार इस राज्य को 'सुजलाम-सुफलाम' बनाना चाहती है, इसलिए कृषि प्रक्षेत्र को हमारी सरकार ने उच्च प्राथमिकता दी है। हम सभी जानते हैं कि हमारा राज्य खाद्यान्न के मामले में कमी वाला राज्य है। यहाँ खाद्यान्न की आवश्यकता 45 लाख मिट्रिक टन है जबकि हम लगभग 22 लाख मिट्रिक टन खाद्यान्न का ही उत्पादन कर पाते हैं। हमें इस अन्तर को मिटाना है। कृषि प्रक्षेत्र के लिए हमने योजना मद में 147.00 करोड़ रू. का प्रावधान किया है और अनुमान लगाया है कि वित्तीय वर्ष 2007-08 में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़कर 34 लाख 71 हजार मिट्रिक टन हो जायेगा। कृषि के क्षेत्र में बीज विनियमन कार्यक्रम, बीज ग्राम की स्थापना, वैकल्पिक फसल योजना, वर्षा जल के संचयन एवं समुचित उपयोग हेतु सरकार कदम उठा रही है। चतरा जिलें में कृषि प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना करने का विचार है जिससे उस क्षेत्र के लोगों को कृषि संबंधी तकनीकी जानकारियाँ मिल सकेंगी। दुमका जिले में भी इसी तरह के एक पार्क की स्थापना का प्रस्ताव है। कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2007-08 में गोड्डा जिले में एक कृषि महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। किसानों को समय पर सही बीज मिले, खाद मिले और सिंचाई के लिए पानी हर खेत में पहुँचे, इसके लिए सरकार प्रयत्नशील है, जिससे कृषि में आशातीत बढ़ोत्तरी हो सके।

5. अध्यक्ष महोदय, कृषि के साथ-साथ सहकारिता क्षेत्र को जोड़ने की भी आवश्यकता है क्योंकि दोनों ही एक-दूसरे के पूरक हैं। सहकारिता प्रक्षेत्र के लिए वित्तीय वर्ष 2007-08 में 150.00 करोड़ की योजना का उद्व्यय रखा गया है। समेकित शहरी विकास परियोजना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए संयुक्त सहकारी समितियों का गठन तथा संयुक्त सहकारी समितियों के माध्यम से सब्जी उत्पादन और आहरण एवं लघु वन उपज के आहरण (Processing) पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

6. अध्यक्ष महोदय, कृषि से ही जुड़ा हुआ पशुपालन तथा मत्स्य पालन प्रक्षेत्र है जिसमें वित्तीय वर्ष 2007-08 में 91.70 करोड़ रू. का योजना उद्व्यय रखा गया है।

पशुपालन को तकनीकी आधार प्रदान करते हुए इसे उद्योग के रूप में विकसित करने का विचार है, जिसमें गाय-भैंस का विकास, सूकर विकास, कुक्कुट विकास तथा उनके चारे के विकास का कार्यक्रम चलाया जायेगा। दुग्ध उत्पादन के कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। झारखण्ड में मछली पालन भी आय का एक अच्छा स्रोत हो सकता है। यहाँ वर्षा काफी होती है। तालाबों की संख्या भी अच्छी-खासी है। सभी तालाबों में मछली पालन को बढ़ावा दिया जाय, इसकी ओर सरकार प्रयत्नशील है।

7. सिंचाई के बगैर कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना काफी कठिन है, इसीलिए सिंचाई प्रक्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने वित्तीय वर्ष 2007-08 में 529.00 करोड़ रू. की योजना उद्व्यय का प्रावधान किया है। राज्य में वृहद् सिंचाई योजनाएं अपने निर्माण के विभिन्न चरणों में है। इन सभी को पूर्ण करना हमारा लक्ष्य है। स्वर्ण रेखा बहुद्देशीय परियोजना का काम जल्दी पूरा हो, इसके लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है और वित्तीय वर्ष 2006-07 में लगभग 1395 हेक्टेयर जमीन में इस परियोजना से सिंचाई भी हुई है। परन्तु हमारी सरकार लघु सिंचाई को ज्यादा प्राथमिकता देना चाहती है। झारखण्ड में लगभग 1400 मिलीमीटर वर्षा प्रत्येक वर्ष होती है। यदि वर्षा के पानी का संचय कर लिया जाय तो राज्य में सिंचाई के क्षेत्र में क्रान्ति आ जायेगी। इसी अवधारणा को आत्मसात् करते हुए हमारी सरकार लघु सिंचाई को प्रधानता देती है जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2007-08 में 168.10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। लघु सिंचाई से जहाँ एक ओर गाँव के परिवार विस्थापित नहीं हाते वहीं दूसरी ओर कम लागत में और कम समय में उपयोगी योजनायें पूरी हो जाती हैं।

8. ग्रामीण विकास के बिना राज्य के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। अध्यक्ष महोदय, कवि सुमित्रानन्दन पंत ने कहा है कि **'भारत माता ग्रामवासिनी'**। भारत माता गाँवों में बसती है। हमारा राज्य भी गाँवों में ही बसता है इसीलिए ग्रामीण विकास हमारी प्राथमिकताओं में काफी ऊपर है। वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए योजना मद में हमने 546.26 करोड़ रू० रखे हैं। राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कर ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना चाहती है। ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसे "नरेगा" के नाम से जाना जाता है। झारखण्ड के 22 जिलों में 20 जिले इस योजना के तहत् केन्द्र सरकार द्वारा आच्छादित हैं और शेष दो जिलों, देवघर तथा पूर्वी सिंहभूम को राज्य सरकार ने अपने बजट में इस कार्यक्रम के तहत् शामिल किया है। इस योजना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले इच्छुक लोगों को प्रति परिवार साल भर में कम-से-कम 100 दिनों का रोजगार दिये जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2006-07 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 360 लाख मानव दिवसों का सृजन कर रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गाँवों के विकास के लिए लगभग सभी योजनाएँ, जैसे जल स्रोतों का निर्माण, वानिकीकरण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जमीन का विकास करना, बाढ़ एवं सुखाड़ से संबंधित कार्यक्रम चलाना तथा सम्पर्क सड़कों का निर्माण आदि शामिल है। यह कार्यक्रम और मजबूती से लागू हो, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति न केवल "नरेगा" कार्यक्रम की समीक्षा करेगी, बल्कि झारखण्ड की आवश्यकताओं के अनुरूप भारत सरकार को सुझाव भी देगी। अध्यक्ष महोदय, "नरेगा" कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रामबाण औषधि की तरह काम कर रहा है। इससे गांवों में मजदूरों के पलायन में कमी देखने को मिल रही है। इस कार्यक्रम के लिए राज्य स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक 5530 पदों का सृजन कर लिया गया है और तुरंत नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है।

9. अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री ने दिनांक 22 दिसम्बर, 2006 को इस सदन में घोषणा की थी कि सभी माननीय विधायकों की अनुशंसा के अनुसार उनके निर्वाचन क्षेत्र में एक-एक करोड़ रूपये की योजना ली जायेगी। चूंकि अभी समय कम बचा है इसलिए इस वित्तीय वर्ष में 50-50 लाख रूपये प्रति विधानसभा क्षेत्र सभी जिलाधिकारियों को राशि उपलब्ध करा दी जायेगी तथा बाकी राशि अगले वित्तीय वर्ष मे विमुक्त की जायेगी। हमारी सरकार समझती है कि इस राशि से जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्र में और अधिक

विकास का कार्य करा सकेंगे।

10. अध्यक्ष महोदय, गाँवों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2006-07 में जनवरी, 2007 तक 26026 नये मकान बनाकर दिये गये तथा 11145 आवासों का उन्नयन किया गया। हम अगले वर्ष 49000 इंदिरा आवास का निर्माण करना चाहते हैं। फिर भी इंदिरा आवास योजना का लाभ सभी बी.पी.एल. परिवारों तक नहीं पहुँचा पायेंगे। जो बी.पी.एल. परिवार इस योजना से अछूते रह रहे हैं, उनके लिए सिद्धो-कान्हो आवास योजना नाम से एक नयी योजना चलायी जायेगी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत दिनांक- 31.03.2006 तक 29079 स्वयं सेवी समूहों का गठन किया गया था। वित्तीय वर्ष 2006-07 में 8568 स्वयं सेवी समूह गठित किये गये। अगले वित्तीय वर्ष में 9500 स्वयं सेवी समूहों के गठन का लक्ष्य रखा गया है। इन स्वयं सेवी समूहों के माध्यम से समूह के सदस्यों को ऋण आसानी से उपलब्ध हो जाता है और वे उससे अपनी आजीविका कमाने में कामयाब होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये समूह माइक्रो क्रेडिट में एक क्रांतिकारी कदम है।

मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 में 206 करोड़ बजट का प्रावधान जो पिछले साल की राशि से 95 करोड़ ज्यादा है। इसके अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा पुल-पुलिया बनाकर गाँवों को आपस में जोड़ने का कार्यक्रम बनाया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंर्तगत वित्तीय वर्ष 2007-08 में 340 करोड़ रू. व्यय का प्रस्ताव है जबकि राज्य सम्पोषित योजना के अन्तर्गत 150 करोड़ का योजना उद्व्यय प्रस्तावित है। भारत सरकार के सहयोग से चलने वाले इन सभी कार्यक्रमों को राज्य सरकार पूरी तत्परता से लागू करते हुए गाँवों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी।

11. पंचायती राज व्यवस्था गाँवों के विकास से जुड़ी हुई है। जिन कारणों से पंचायत चुनाव नहीं हो रहे हैं, हम सभी उनसे परिचित हैं। इसलिए मैं उन कारणों को दोहराना नहीं चाहता। सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है ताकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में अपना निर्णय अतिशीघ्र दे दे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आते ही हमारी सरकार पंचायत चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है ताकि प्रजातंत्र की प्राथमिक इकाई राज्य के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाकर भारतीय प्रजातंत्र प्रणाली को और मजबूती प्रदान कर सके।

12. अध्यक्ष महोदय, आधारभूत संरचनाओं में पथ का अपना महत्व है। हमारी सरकार ने इस प्रक्षेत्र के लिए 546.96 करोड़ रू. का योजना उद्व्यय अगले वित्तीय के लिए प्रस्तावित किया है। इसमें 474.00 करोड़ पथों के निर्माण तथा विकास के लिए और 72.96 करोड़ पुलों के निर्माण आदि के लिए रखा गया है। राज्य के राजमार्गो के उन्नयन तथा सुदृढ़ीकरण हेतु झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के गठन की कार्रवाई की जा रही है। यह प्राधिकार राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण एवं प्रबंधन को देखेगा और आशा की जाती है कि सड़कों के निर्माण और रख-रखाव की गुणवत्ता में आशातीत वृद्धि होगी। पथों के निर्माण ध सुदृढ़ीकरण के लिए आवश्यक निधि जुटाने के उद्देश्य से सरकार झारखण्ड पथ विकास निधि का गठन करने जा रही है। पथ निर्माण में निजी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए Special Purpose Vehicle का गठन भी किया जा रहा इसके लिए Expression of Interest आमंत्रित किये जा चुके हैं। इस वर्ष लगभग 200 किलोमीटर सड़कों का निर्माण, सुदृढ़ीकरण व विकास किया गया है और अगले वित्तीय वर्ष में 500 किलोमीटर सड़कों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण का का लक्ष्य रखा गया है।

13. अध्यक्ष महोदय, विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं में विद्युत का अपना महत्व है। राज्य सरकार विद्युत उत्पादन, संचरण एवं वितरण में सुधार लाने के लिए प्रयास कर रही है। वित्तीय वर्ष 06-07 में ललपनिया ताप संयत्र में सुधार लाकर 2233 मेगावाट यूनिट का रिकार्ड विद्युत उत्पादन किया गया है। राज्य गठन के पश्चात् सिकिदरी पनबिजली संयत्र से भी, सबसे अधिक 207 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन हुआ है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में राज्य प्रक्षेत्र में 3000 मेगावाट तथा निजी प्रक्षेत्र में 4000 मेगावाट अतिरिक्त उत्पादन क्षमता बढ़ाना सरकार का लक्ष्य है।

हमारी सरकार के प्रयास से केन्द्र सरकार द्वारा हजारीबाग जिले के बरही प्रखण्ड में 4000 मेगावाट की क्षमता वाला अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट लगाने का निर्णय लिया है। वित्तीय वर्ष 2007-08 में 902.53 करोड़ रूपये की उद्व्यय राशि में से उत्पादन, वितरण एवं संचरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए 457 करोड़ रूपये के व्यय का प्रावधान किया गया है।

14. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भारत सरकार को भेजा जा चुका है जिसमें 11 जिलों की योजना केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत कर दी गयी है। डी.वी.सी. को 5572 गाँवों, एन.टी.पी.सी. को 8705 गाँवों तथा ज.एस.ई.बी. को 5530 गाँवों के विद्युतीकरण का कार्य दिया गया है। बाकी जिलों की स्वीकृति के लिए भी सरकार प्रयासरत है और आशा है कि अगले कुछ महीनों में सभी जिले की योजनाओं पर स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। ग्रामीण विद्युतीकरण का काम दामोदर घाटी निगम, एन.टी.पी.सी. तथा झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड, द्वारा किया जा रहा है। तीनों ही एजेंसियों ने अपना अपना काम शुरू कर रखा है। ऐसी आशा है कि ग्राम विद्युतीकरण का यह कार्य 2009 तक पूरा कर लिया जायेगा।

15. अध्यक्ष महोदय, आप अवगत हैं कि झारखंड खनिज पदार्थों से परिपूर्ण है परन्तु अभी तक एकाध को छोड़कर कोई बड़ा उद्योग यहां स्थापति नहीं हो पाया है। अब औद्योगिक घरानों ने झारखण्ड में उद्योग लगाने में दिलचस्पी दिखायी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अनेक औद्योगिक घरानों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर (एम.ओ.यू.) भी हुए हैं। निस्संदेह यहां के नवयुवकों को जब तक तकनीकी शिक्षा नहां दी जायेगी, तब तक भविष्य में लगनेवाले उद्योगों में उन्हें नौकरियाँ नहीं मिल पायेंगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने तकनीकी शिक्षा को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। इस कड़ी में वित्तीय वर्ष 07-08 में 3 अभियंत्रण महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये अभियंत्रण महाविद्यालय रामगढ़, चाईबासा तथा दुमका में खोले जायेंगे। साथ ही साथ 8 नये पॉलटेनिक संस्थान स्थापित करने का भी निर्णय सरकार ने लिया है। इसके अतिरिक्त पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अवधारणा के अन्तर्गत इंजीनियरिंग कॉलेजों/संस्थानों को स्थापित करने का भी प्रयास किया जायेगा।

16. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार झारखंड में उद्योग स्थापित करना चाहती है। खलारी सीमेंट फैक्ट्री जो वर्षों से बंद पड़ी थी, सरकार ने उसे पुनः चालू करा दिया है। जिंदल स्टील एवं पावर लिमिटेड द्वारा 6 मीलियन टन क्षमता वाले इस्पात संयंत्र पर निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। इसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 18.03.07 को किया गया है। आशा है कि यह इस्पात संयंत्र शीघ्र ही चालू हो जायेगा। यह प्रयास किया जा रहा है कि जो समझौते हो चुके हैं वे सरजमीं पर अपना स्वरूप लें।

17. अध्यक्ष महोदय, उद्योग तो लग जाते हैं परन्तु ग्रामीण परिवार बेघर हो जाते हैं। एच.ई.सी. का मसला हो या फिर बोकारों स्टील लिमिटेड का या फिर स्वर्णरेखा परियोजना का, विस्थापन की पीड़ा हम आज भी महसूस कर रहे हैं सैकड़ों परिवार घर से बेघर हो गये हैं। और अधिक परिवार विस्थापित न हों, इसके लिए हमारी सरकार सजग है। इसी परिप्रेक्ष्य में एक ऐसी सर्वमान्य पुनर्वास नीति की आवश्यकता है जिसमें न केवल प्रभावित परिवारों का बल्कि उस क्षेत्र का समग्र विकास हो। साथ ही पुनर्वास नीति में प्रभावित परिवारों का न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य भी सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार पुनर्वास नीति पर गंभीरता से विचार कर रही है और हम शीघ्र ही इस नीति की घोषणा करेंगे।

18. अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मनुष्य के विकास की एक अहम कड़ी है। शिक्षा के बगैर मनुष्य अधूरा है। मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार शिक्षा को उच्चतम प्राथमिकता देती है और इसीलिए सरकार ने वित्तीय वर्ष 07-08 के लिए 538.48 करोड़ रुपये का उद्व्यय रखा है।

19. शिक्षा के क्षेत्र में, हमारी सराकर ने अल्पावधि में ही कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये है। संस्कृत तथा मदरसा विद्यालयों के शिक्षकों को अभी तक मात्र 74 प्रशित की दर से महंगाई भत्ता दिया जाता रहा है जबकि उन्हें 334 प्रतिशत दिया जाना चाहिए था। हमारी सरकार ने इस विद्यालय के

शिक्षकों को 334 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया है। हम सभी जानते हैं कि अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाएं शिक्षा के क्षेत्र में झारखण्ड राज्य में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। हम सभी यह बात भली-भांति जानते हैं कि शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें राज्य के साथ-साथ समाज की भी भागीदारी हो तो शिक्षा प्रसार का काम और आसान हो जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में अल्पसंख्यक संस्थाओं के योगदान को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने प्राथमिक एवं माध्यमिक अल्पसंख्यक शिक्षकों तथा शिक्षकेतर कर्मचारियों को सरकारी शिक्षकों तथा शिक्षकेतर कर्मचारियों की तरह वेतनमान देने पर विचार कर रही है।

20. अध्यक्ष महोदय, राज्य में पाँच प्रमंडल हैं। कोल्हान प्रमंडल को छोड़कर बाकी सभी प्रमंडलों में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा चुकी है। कोल्हान प्रमंडल शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ प्रमंडल है इसलिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि कोल्हान प्रमंडल में भी एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो। सरकार कोल्हान में विश्वविद्यालय स्थापित करने की सभी कार्यवाही अगले वित्तीय वर्ष में पूरा करने का विचार रखती है।

21. अध्यक्ष महोदय, सरकार चाहती है कि शिक्षक विद्यालयों में जायें, समय पर जायें, रोजाना जायें, इसीलिए शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नयी पुरस्कार योजना लागू की जायेगी जिसके अन्तर्गत प्रखंड स्तर से लेकर राज्य स्तर तक पुरस्कार की व्यवस्था रहेगी। वित्तीय वर्ष 07-08 में इस प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए दो करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

22. ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को आधुनिक तथा कम्प्यूटर आधारित शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कम्प्यूटर शिक्षा को विस्तारित किया जा रहा है। इस क्रम में राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। इसके तहत 750 विद्यालयों में चरणबद्ध रूप से यह योजना लागू की जायेगी, इसके लिए वर्ष 2007-08 में 12 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान किया जा रहा है।

23. राज्य में लगने वाले उद्योगों एवं कारखानों के लिए कुशल मानव बल उपलब्ध कराने तथा रोजगार के नये अवसर हेतु कक्षा 9 से 12 में व्यावसायिक शिक्षा को प्रभावी तरीके से लागू किया जायेगा। इसके तहत स्थानीय औद्योगिक संस्थानों से समन्वय कर व्यावसायिक शिक्षा के नये Trades में शिक्षण कार्य प्रारंभ किये जायेंगे। वित्तीय वर्ष 2007-08 में इस योजना के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

24. अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में **सर्व शिक्षा अभियान** एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हमने इसमें सराहनीय कार्य किया है। वित्तीय वर्ष 06-07 में हमने 5159 शिक्षा गारंटी केन्द्रों का प्राथमिक विद्यालय में तथा 1585 प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालयों में उत्क्रमित किया है। राज्य के 212 प्रखंडों में से 155 प्रखंडों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं। इन विद्यालयों में शिक्षा से वंचित 11 हजार से अधिक बालिकाएं आवासीय रूप में शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। बच्चों की शिक्षा को देखते हुए 15485 अतिरिक्त पारा शिक्षकों का चयन ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा किया गया है। 206 सरकारी मध्य विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा कार्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं। अगले वित्तीय वर्ष में 2155 प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालयों में उत्क्रमित करना, प्रत्येक 3 किलोमीटर के अन्दर मध्य विद्यालय की सुविधा पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। 5 हजार नये भवनों तथा 15 हजार अतिरिक्त कमरे के निर्माण का भी कार्यक्रम है। अगले वित्तीय वर्ष में 32 और प्रखंडों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्थापित किये जायेंगे। राज्य सरकार इन विद्यालयों में कक्षा 9 तथा 10 तक की पढ़ाई शुरू करने पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। अभी तक हमारे 58 लाख 20 हजार बच्चे शिक्षा से जुड़ चुके हैं और 3 लाख 66 हजार बच्चे अभी भी शिक्षा से वंचित हैं। सरकार का प्रयास रहेगा कि इन सभी को शिक्षा के साथ जोड़ा जाय। सर्व शिक्षा अभियान का एक नारा मैं यहां दोहराना चाहूँगा :

"नव वर्ष में हम सबका हो ऐसा प्रयास,
शिक्षा पहुँचाये सब बच्चों के पास।"

25. भारत सरकार की NCERT की तर्ज पर राज्य सरकार

द्वारा SCERT के गठन का निर्णय लिया गया है। यह संस्था शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्धारण करेगी और साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए सभी कारगर उपाय करेगी जिसमें प्रशिक्षण एवं शोध भी शामिल रहेगा। अब पुस्तकों के लिए राज्य सरकार को एन.सी.ई.आर.टी. पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

26. झारखण्ड के बंगलाभाषी लोग काफी दिनों से बंगला अकादमी की स्थापना की मांग करते रहे हैं। राज्य सरकार ने बंगला अकादमी की स्थापना का निर्णय लिया है और शीघ्र ही यह अकादमी अपने पूर्ण स्वरूप में कार्यरत हो, इसके लिए सभी आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं।

27. अध्यक्ष महोदय, हम सभी स्वस्थ्य रहना चाहते हैं, इसके लिए तरह-तरह के उपाय भी करते हैं। फिर भी यदा-कदा हर किसी को किसी न किसी रोग का सामना करना ही पड़ता है। स्वाथ्य प्रक्षेत्र हमारी सरकार की प्राथमिकताओं का एक अभिन्न अंग है। वित्तीय वर्ष 2007-08 में हमने इस प्रक्षेत्र के लिए 281 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। यह बात सही है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने चिकित्सकों तथा पारा मेडिकल स्टाफ को अनुबंध के आधार पर रखकर गाँव-गाँव तक स्वास्थ्य सेवा पहुँचाने का प्रयास किया है परन्तु इस बात को भी हम स्वीकार करते हैं कि अभी इस प्रक्षेत्र में बहुत कुछ करना बाकी है। राज्य में 7088 स्वास्थ्य उप-केन्द्रों, 1126 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 188 सामुदायिक केन्द्रों की आवश्यकता है परन्तु वर्तमान में 3958 स्वास्थ्य उप केन्द्र, 330 अतिरिक्त-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 193 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ही उपलब्ध हैं। सरकार अगले 5 वर्षों में सभी स्वास्थ्य उप-केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण करना चाहती है। वित्तीय वर्ष 2007-08 में 180 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 330 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 2000 स्वास्थ्य उप-केन्द्र बनाने का कार्यक्रम है, यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

28. अध्यक्ष महोदय, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जननी-शिशु स्वास्थ्य योजना लागू की गयी है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को सुरक्षित संस्थागत प्रसव एवं शिशुओं के पूर्ण टीकाकरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2006-07 में अभी तक 89237 गर्भवती महिलाओं को इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ पहुँचाया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2007-08 में इस योजना के अंतर्गत 3 लाख महिलाओं को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य सेवाओं में समाज की भागीदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 'सहिया' कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 'सहिया' समुदाय समाज तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के बीच एक सेतु का काम करती है। यह कार्यक्रम अभी 59 प्रखंडों में चलाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2007-08 में इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी प्रखंडों को सम्मिलित करने का लक्ष्य रखा गया है।

29. महिलाओं में रक्त की कमी जिसे 'एनिमिया' के नाम से भी जाना जाता है, एक बड़ी समस्या है। एक अनुमान के अनुसार राज्य में प्रजनन आयु की लगभग 78 प्रतिशत महिलाएं 'एनिमिया' से ग्रसित हैं। इस वर्ष गुमला जिले में इस समस्या से निजात पाने के लिए एक पायलट कार्यक्रम चलाया जा रहा है और उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2007-08 में राज्य के 6 अन्य जिलों, देवघर, दुमका, पाकुड़, हजारीबाग, गढ़वा तथा लातेहार शामिल हैं, में इस कार्यक्रम को लागू किया जायेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पारा मेडिकल स्टाफ की अहम् भूमिका है, परन्तु हमारे राज्य में पारा मेडिकल स्टाफ की बहुत ही कमी है। राज्य के 10 जिलों में ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्रों तथा छात्र प्रशिक्षण केन्द्रों को कार्यशील बनाया गया है। वर्ष 2007-08 में राज्य के शेष बचे 12 जिलों में भी ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्रों को कार्यशील बनाने की योजना है।

30. अध्यक्ष महोदय, राज्य के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को निजी क्षेत्र के माध्यम से स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु जिस सर्व स्वास्थ्य मिशन का सूत्रण इस वर्ष किया गया है, उसे पायलट आधार पर वित्तीय वर्ष 2007-08 में राज्य के 2 प्रखंडों में चालू कर दिया जायेगा।

31. हम सभी जानते हैं कि राज्य में चिकित्सकों की बड़ी कमी है, इस कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची में नामांकण हेतु प्रति वर्ष

90 सीट को बढ़ा कर 250 सीट कर दिया गया है। पाटलीपुत्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल, धनबाद में सीटों की संख्या 50 से 100 कर दी गयी है। इसी प्रकार महात्मा गाँधी मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर में भी 50 सीटों को बढ़ा कर 100 किया जा रहा है। राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची में एक दंत चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के पास विचारधीन है। रिम्स, राँची में नर्सिंग में बी.एस.सी. की डिग्री की पढ़ाई हेतु नर्सिंग कॉलेज खोलने का भी सरकार का विचार है। अस्पताल में सुपरस्पेशलिस्टी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से न्यूरोलॉजी, कार्डिलॉजी, यूरोलॉजी, कार्डियोथेरेपी, कैंसर तथा टोन्टोलॉजी की संकायें खोलने का सरकार का विचार है। राँची सदर अस्पताल को 500 शय्या वाले अस्पताल के रूप में विकसित करने पर भी सरकार कार्रवाई कर रही है।

32. पाटलीपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, धनबाद तथा महात्मा गाँधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जमशेदपुर के Interns, गृह चिकित्सक तथा स्नातकोत्तर छात्र अपनी छात्रवृत्ति की वृद्धि के लिए सरकार से बार-बार आग्रह कर रहे थे। सरकार ने महँगाई तथा छात्रों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इनकी छात्रवृत्ति बढ़ाने का निर्णय लिया है। Interns की छात्रवृत्ति 2750 रुपये से बढ़ा कर 3750 रुपये, गृह चिकित्सक की छात्रवृत्ति 4000 रुपये से बढ़ा कर 4750 रुपये तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष छात्र की छात्रवृत्ति 7300 रुपये से 10.000 रुपये तथा स्नातकोत्तर तृतीय वर्ष के छात्रों की छात्रवृत्ति 7800 रुपये से बढ़ा कर 10.800 रुपये प्रतिमाह की गयी है।

33. अध्यक्ष महोदय, शुद्ध जल प्राप्त नहीं होने के कारण, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, आम लोग अनेकों बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, इसलिए हमारी सरकार का प्रयास है कि हम सभी को शुद्ध जल उपलब्ध करायें। वित्तीय वर्ष 2007-08 में राज्य योजना के अंतर्गत 205 करोड़ रुपये और केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत 151.805 करोड़ रुपये का योजना उद्व्यय रखा गया है। राज्य में नलकूपों पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से ग्रामीण जलापूर्ति पर जोर दिया जा रहा है। पूरे राज्य का सर्वेक्षण कराकर एक वृहद योजना बनायी जायेगी, जिसके अंतर्गत सभी गाँव-टोलों में ग्रामीण जलापूर्ति के माध्यम से सभी को शुद्ध जल उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जायेगी। हम आशा करते हैं कि यह योजना 5 साल और होगी और इस अवधि में गाँव-गाँव, टोले-टोले में नल का पानी पहुँचाने की सरकार की योजना है। जिन क्षेत्रों में फ्लोराईड तथा आर्सेनिक की समस्या है वहाँ इन दोनों ही रसायनों को साफ करने के लिए प्लांट स्थापित करने की योजना है।

34. 'सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान' के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2006-07 में जनवरी, 2007 तक 1.11.884 घरेलू शौचालय, 3416 विद्यालय शौचालय तथा 12 सामुदायिक शौचालय कम्प्लेक्सों का निर्माण कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2007-08 में राज्य के सभी प्रखंडों में अवस्थित प्रखंड मुख्यालय पंचायत तथा 400 अन्य पंचायतें निर्मल ग्रामीण पुरस्कार प्राप्त करने की स्थिति में आ जायेगी।

35. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा में शामिल करने का हर संभव प्रयास कर रही है। कुल आबादी में इन समुदायों की जनसंख्या देखी जाय तो लगभग 70-80 प्रतिशत की आबादी इसमें शामिल हो जाती है। निःसंदेह किसी भी राज्य या राष्ट्र का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक इन पिछड़े वर्गों को समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं किया जाय। इसी परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा इन वर्गों की बेहतरी के लिए अनेकों कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जिनमें छात्रों को छात्रवृत्ति, छात्रावासों का निर्माण एवं संचालन, आवासीय विद्यालयों का संचालन, बिरसा आवास योजना, हड़गड़ी/मसना/जाहेरथान एवं कब्रिस्तानों की घेराबंदी, व्यवसायिक प्रशिक्षण, साइकिलों का वितरण आदि शामिल है। वित्तीय वर्ष 2007-08 में इस प्रक्षेत्र के लिए 500.54 करोड़ रुपये का योजना उद्व्यय निर्धारित किया गया है। यदि इनकी छात्रवृत्ति की ही बात करें तो वर्ष 2006-07 में 28 लाख 43 हजार 453 छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा रही है जिनकी संख्या बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2007-08 में लगभग 35 लाख हो जायेगी।

36. अनुसूचित जनजाति में आदिम जनजातियों की स्थिति और भी भिन्न है। ये पिछड़ेपन के दृष्टि से सबसे कमजोर है,

इसलिए हमारी सरकार इनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है। सरकार ने आठ आदिम जनजाति विद्यालय बनाये हैं जिसे वित्तीय वर्ष 2007-08 में गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से चलाने का कार्यक्रम है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि विकास एक ऐसी यात्रा है जिसमें सभी की सहभागिता आवश्यक है और इसी बात को ध्यान में रखकर आदिम जनजाति के विद्यालयों को सरकार ऐसे गैर सरकारी संगठनों को देने जा रही है जो शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं।

37. अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि सरकार ने अनूसूचित जनजाति के 25 छात्रों को पायलट का प्रशिक्षण दिया था जिसमें से 21 को विभिन्न एयरलाइन्सों में नौकरी मिल चुकी है। अगले वर्ष 30 छात्रों को पायलट का प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम है। बिरसा आवास योजना जिसके अंतर्गत आदिम जनजातियों को आवास उपलब्ध कराये जाते है।, वित्तीय वर्ष 2006-07 में 2750 आवासों का निर्माण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2007-08 में 3500 बिरसा आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

38. इस्लाम मतावलम्बियों के लिए हज यात्रा एक बहुत ही पवित्र कार्य है। इस्लाम को मानने वाले पूरे देश से लाखों यात्री हज यात्रा के लिए पवित्र शहर मक्का जाते हैं। झारखण्ड से भी हजारों लोग हज यात्रा में जाते हैं परन्तु अभी तक झारखण्ड में एक भी हज हाउस नहीं बन पाया है। हज यात्रियों को सुविधा देने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने राँची में एक हज हाउस बनाने का निर्णय लिया है।

39. अध्यक्ष महोदय, राज्य में काफी वक्फ सम्पत्तियाँ है परन्तु उनके प्रबन्धन और देख-रेख की कोई व्यवस्था नहीं है। इन पर अनधिकृत लोग कब्जा जमा रहे हैं। सरकार ने इनके प्रबंधन तथा उचित देख-रेख के लिए झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड के गठन करने का निर्णय लिया है।

40. अध्यक्ष महोदय, नगर विकास प्रक्षेत्र को भी राज्य सरकार ने काफी गंभीरता से लिया है। नगर निकायों के क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को सड़कों एवं पुल, पेयजल आपूर्ति, शहरी गरीबी उन्मूलन तथा विभिन्न प्रकार की नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य चलाये जाने का निर्णय लिया है। वर्ष 2006-07 में नगर विकास के लिए 255 करोड़ रुपये का योजना उद्व्यय निर्धारित था परन्तु वर्ष 2007-08 में इसे बढ़ाकर 345 करोड़ रुपये के योजना उद्व्यय का प्रस्ताव है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 90 करोड़ अधिक है। इसके अंतर्गत नगर क्षेत्र में परिवहन योजनाओं को और अधिक सशक्त तथा प्रभावशाली बनाने, शहरी जलापूर्ति को सुदृढ़ करने, राँची शहर के सिवरेज/ड्रेनेज प्रणाली को सुदृढ़ करने की कार्रवाई करने, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना को चलाने तथा शौचालय परिवर्तन/निर्माण जैसे कार्य लिये जायेंगे।

41. अध्यक्ष महोदय, सरकार नगर निकायों का चुनाव कराने के लिए तत्पर है। तत्संबंधी निर्वाचन नियमावली को अधिसूचित भी कर दिया गया है। सरकार ने राज्य रिर्वाचन आयोग से नगर निकायों के चुनाव शीघ्रातिशीघ्र कराने के लिए अनुरोध किया है। अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के क्रम में केन्द्र सरकार ने राँची तथा दूसरे शहरी क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र से बाहर रख दिया था। निःसंदेह इससे अनुसूचित जनजातियों के हितों की उपेक्षा होती। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस मामले को भारत सरकार के साथ पूरी गंभीरता से उठाया। मुझे खुशी है कि केन्द्र सरकार ने तत्संबंधी अपनी अधिसूचनाओं को संशोधित करते हुए राँची तथा दूसरे शहरी क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्रों में शामिल कर लिया है।

42. अध्यक्ष महोदय, राजस्व एवं भूमि सुधार के लिए वर्ष 2007-08 में 15 करोड़ रुपये योजना उद्व्यय का प्रस्ताव है। इसके अंतर्गत सर्वे एवं बंदोबस्ती के कार्य, भू-धारी खाता पुस्तिका के कार्य, अनुसूचित जनजाति के लोगों की भूमि के अवैध अंतरण को रोकने हेतु मुकदमें लड़ने के लिए वैधिक अनुदान तथा भूमि वापसी के बाद उसके विकास हेतु आर्थिक सहायता दिये जाने जैसे कार्यक्रम चलाये जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त सैरात के अंतर्गत हाट बाजार मेला आदि के विकास के लिए भी राशि का प्रावधान किया गया है। राजस्व प्रशासन सुदृढ़ करने के लिए राजस्व अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य आरंभ किया गया है, जिससे किसानों को काफी सुविधा होगी।

43. अध्यक्ष महोदय, इस राज्य में लगभग 24 लाख बी.पी.

एल. परिवार हैं। इन सभी परिवारों को सरकार आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध कराती है। यह कार्यक्रम अगले वित्तीय वर्ष में भी चालू रहेगा। 24 लाख बी.पी.एल. परिवारों में से 9 लाख परिवार अंत्योदय योजना के अंतर्गत खाद्यान्नों का लाभ प्राप्त करते हैं, जबकि बाकी बचे हुए लगभग 15 लाख सामान्य बी.पी.एल. योजना के अंतर्गत लाभान्वित होते हैं। अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत लगभग दो लाख लोगों को सुविधाएँ प्रदान की जाती है। राज्य में खाद्यान्नों के भंडारण की काफी कमी है। इसलिए अगले वित्तीय वर्ष में खाद्यान्नों के भंडारण की सुविधा बढ़ाने का भी प्रयास किया जायेगा। जन वितरण दुकानों के संबंध में बराबर शिकायतें मिलती रहती हैं। सरकार ने जन वितरण शिकायत निवारण आयोग का गठन करने का निर्णय ले लिया है।

44. अध्यक्ष महोदय, झारखण्ड एक रमणीक प्रदेश है। यहाँ हजारों की संख्या में पर्यटक स्थल है। एक ओर जहाँ एशिया का सबसे सुन्दर सारंडा वन क्षेत्र है वहीं दूसरी ओर हर जिले में झील-झरने भी हैं। तीर्थाटन के भी अनेकों स्थल हैं। इसलिए झारखण्ड में पर्यटन आमदनी का एक बहुत बड़ा स्रोत हो सकता है। पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने कुछ कार्य किये हैं परन्तु इनका वैज्ञानिक तरीके से विकास करने के लिए हमारी सरकार ने झारखण्ड राज्य के सभी पर्यटन स्थलों का सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है। सर्वेक्षण के पश्चात् सभी पर्यटन स्थलों का वर्गीकरण किया जायेगा और एक समयबद्ध तथा चरणबद्ध तरीके से सभी को विकसित करने की योजना बनायी जायेगी।

45. अध्यक्ष महोदय, झारखण्ड राज्य को 34वीं राष्ट्रीय खेल की मेजबानी मिली है। हम उसके लिए सभी तैयारी कर रहे हैं। झारखण्ड में खेलकूद की प्रतिभा प्रचुरता में दिखायी दे रही है। 33वीं राष्ट्रीय खेल में हमारे खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण, 9 रजत तथा 7 कांस्य पदक जीते हैं। हम पूरे सदन की ओर से इन सभी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई देते हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय महिला महोत्सव में राज्य की महिला हॉकी टीम को स्वर्ण पदक मिला है इसके लिए भी महिला हॉकी टीम को हम बधाई देते हैं। हमारे खिलाड़ी आनेवाले राष्ट्रीय खेल में अधिक से अधिक पदक जीत सके, इसके लिए सरकार ने खिलाड़ियों के उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। उन्हें बढ़िया उपकरण दिये जा रहे हैं और उच्च कोटि के प्रशिक्षकों की व्यवस्था की जा रही है। खिलाड़ियों को अभ्यास का पूरा मौका मिले, इसके लिए विभिन्न खेलों में टूर्नामेंट की भी व्यवस्था की जा रही है। सभी प्रमंडलों, जिलों, अनुमंडलों और प्रखंडों में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक स्टेडियम का निर्माण किया जायेगा। खेलों को उचित बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने खेल नीति बनाने का भी निर्णय लिए है, जिसके अधीन खेल को गाँव स्तर से लेकर राज्य स्तर तक बढ़ाने की व्यवस्था रहेगी और खिलाड़ियों के लिए अनेकों प्रकार के प्रोत्साहन शामिल रहेंगे, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में सीधी नियुक्ति भी शामिल है।

46. अध्यक्ष महोदय, युवा वर्ग राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग है। हमारी सरकार ने युवा नीति के गठन का भी निर्णय लिया है जिसमें युवाओं से संबंधित सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जायेगा ताकि वे अपनी क्षमता के अनुसार विकसित हो सकें और राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।

47. अध्यक्ष महोदय, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग सरकार के विकास एवं अन्य कार्यों की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा प्रिंट मीडिया के साथ सरकार का ज्यादातर संबंध इसी विभाग के माध्यम से होता है परन्तु राज्य की राजधानी होते हुए भी इस महत्वपूर्ण विभाग के लिए कोई उपयुक्त भवन उपलब्ध नहीं है। इसी परिप्रेक्ष्य में ऑड्रे हाउस काम्पलेक्स में 6.88 करोड़ रुपये की लागत से एक अत्याधुनिक सूचना भवन बनाने का निर्णय लिया गया है। आशा करते हैं कि यह भवन मीडिया और सरकार के बीच संबंधों को नये आयाम तक पहुँचायेगा।

48. अध्यक्ष महोदय, झारखण्ड नया राज्य है इसलिए भवन निर्माण का अपना महत्व है। वित्तीय वर्ष 2007-08 में 79 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। 34वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए भवन निर्माण विभाग पहले ही मेगा स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स तथा खेलगाँव के निर्माण का कार्य कर रहा है। अगले वित्तीय वर्ष में दुमका में उपराजधानी की भवन संरचना का काम हाथ में लिया जायेगा। साथ ही

राँची-डाल्टनगंज तथा राँची-पतरातु सड़कों के बीच में नयी राजधानी के विकास हेतु वास्तुविद तथा डिजाइन का कार्य प्रारंभ किया जायेगा। सरकारी पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए 1500 नये आवास बनाने का प्रस्ताव है। राँची में अतिथिगृह बनाने का भी अगले साल कार्यक्रम है।

49. अध्यक्ष महोदय, झारखण्ड में लगभग 30 प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित है। वित्तीय वर्ष 2007-08 में इस प्रक्षेत्र के लिए 105 करोड़ रुपये का योजना उद्व्यय रखा गया है जिसके अंतर्गत 25 हजार 7 सौ 15 हेक्टेयर वन-भूमि में 4 करोड़ 9 लाख 40 हजार पौधों का वृक्षारोपण किया जायेगा। अगले वित्तीय वर्ष में समेकित वन एवं ग्राम विकास योजना के नाम से एक नयी योजना शुरू की जा रही है जिसके अंतर्गत वनों तथा उसके आसपास के गाँवों के विकास के लिए माइक्रो प्लान तैयार कर वनों तथा गाँवों का विकास कराने का कार्यक्रम है।

50. अध्यक्ष महोदय आप जानते हैं कि भारत सरकार ने The Schedule Tribes and Other Traditional Dwellers (Recogntion of Forest Rights) ACt, 2006 पारित किया है जिससे वनों में रहनेवाले लोगों को काफी राहत मिलेगी। हम भारत सरकार के इस कदम की सराहना करते हैं और उन्हें साधुवाद भी देते हैं। हमारी सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने का सतत् प्रयास करेगी।

51. अध्यक्ष महोदय, राज्य से बाहर हजारों की संख्या में हमारे श्रमिक काम पर जाते हैं परन्तु उन राज्यों में उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है, उससे हम सभी भली-भाँति वाकिफ हैं। ऐसे श्रमिकों की सहायता के लिए दिल्ली में झारखण्ड भवन में एक हेल्प-लाइन शुरू की जा रही है। हम आशा करते हैं कि इस हेल्प-लाइन का उपयोग जरूरतमंद श्रमिक करेंगे और राज्य सरकार ससमय उनकी सहायता कर पायेगी।

52. अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 3 लाख 66 हजार 236 लोगों को वृद्धावस्था पेंशन दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ राज्य सरकार वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 2 लाख 31 हजार 671 अतिरिक्त वृद्धों को पेंशन दे रही है। भारत सरकार ने अपनी योजना के अंतर्गत इस पेंशन राशि को 200 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। राज्य सरकार ने भी अपने वृद्धावस्था पेंशनधारियों को प्रतिमाह 400 रुपये पेंशन देने का निर्णय लिया है।

53. अध्यक्ष महोदय, जब तक राज्य में नक्सलवाद पर काबू नहीं पा लिया जाता है तब तक राज्य के पूर्ण विकास में कठिनाईयाँ आती रहेंगी। हाल ही में माननीय सांसद श्री सुनील महतो की कायरतापूर्ण हत्या से हम सभी मर्माहत हैं। इसीलिए सरकार नक्सलवाद पर काबू पाने के लिए कृत संकल्प है। निस्संदेह इसके लिए न केवल पुलिस प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त बनाना होगा, बल्कि थानों की संख्या भी बढ़ानी होगी और पुलिस बल में भी आवश्यकतानुसार वृद्धि करनी होगी। हमारी सरकार ने हाल ही में तृतीय रिजर्व बटालियन सृजित करने की स्वीकृति दी है। और मैं आशा करता हूँ कि यह बटालियन शीघ्र ही संगठित हो जायेगा। आवश्यकता को देखते हुए 123 थाने और 73 ओ०पी० तथा 10 टी.ओ. पी. खोलने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार विचार कर रही है। प्रथम चरण में सरकार ने 69 थाने तथा 41 ओ.पी. खोलने का निर्णय लिया है। बाकी 54 थाने, 32 ओ.पी. तथा 10 टी.ओ.पी. द्वितीय चरण में स्थापित किये जायेंगे। संचार-तंत्र को भी और मजबूत बनाया जा रहा है। अभी नक्सलियों के प्रत्यर्पण हेतु सरकार की जो नीति है, अनुभव यह बताता है कि वह उतनी कारगर नहीं हुई जितनी कि आशा थी। इसीलिए सरकार इस नीति की भी समीक्षा कर रही है और शीघ्र ही नयी नीति की घोषणा की जायेगी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी। इन क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कों के निर्माण व उनकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। सरकार के इन सभी उपायों से, पुलिस प्रशासन से संबंधित इन कदमों तथा विकास कार्यों से हम सभी उम्मीद करते हैं कि हम नक्सलवाद पर काबू पा लेंगे।

54. अध्यक्ष महोदय, अभी तक मैंने विकास के अनेक कार्यक्रमों की चर्चा की है। विकास के लिए साधन स्रोत जुटाना भी सरकार का एक अहम् कर्त्तव्य है।

55. अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2007-08 में विभिन्न स्रोतों से 16 हजार 1 सौ 72 करोड़ रुपये की आमदनी का अनुमान लगाया गया है, जिसमें राजस्व प्राप्ति के रूप में 11 हजार 6 सौ 12 करोड़ रुपये, कर्ज के माध्यम से 4 हजार 5 सौ 46 करोड़ रुपये तथा ऋण की वापसी से 14 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है।

56. अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2007-08 में राज्य सरकार के कुल राजस्व प्राप्ति में गत वर्ष की तुलना में 1 हजार 4 सौ 68 करोड़ रुपये वृद्धि होने का अनुमान है। इस वृद्धि के साथ राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति 11 हजार 6 सौ 12 करोड़ रुपया हो जायेगी। इनमें केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्सा के रूप में झारखण्ड को 4 हजार 7 सौ 95 करोड़ रुपये मिलने की आशा है। राज्य के निजी करों से 3 हजार 5 सौ 51 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है। राज्य के अभिन्न-कर से 1 हजार 5 सौ 99 करोड़ रुपये की आय होने की संभावना है। राज्य के साधन स्रोत में केन्द्र से प्राप्त होने वाला अनुदान एक महत्वपूर्ण आय स्रोत है। इस मद में राज्य सरकार को 1 हजार 6 सौ 67 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान लगाया गया है।

57. योजना आयोग द्वारा राज्य सरकार के राजस्व में अगले वित्तीय वर्ष के लिए 13.05 प्रतिशत की वृद्धि की अनुशंसा की गयी है, परन्तु बेहतर कर संग्रहण के माध्यम से हम उम्मीद करते हैं कि यह वृद्धि 14.47 प्रतिशत हो जायेगी।

58. राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए अपने अभिन्न कर-राजस्व में 11.55 प्रतिशत वृद्धि के साथ 1 हजार 5 सौ 99 करोड़ के राजस्व संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है।

59. राज्य की विकास योजना निरंतर चलती रहे, इसके लिए सरकार प्रयत्नशील है। विकास योजनाओं के लिए साधन स्रोत की कोई कमी नहीं होने दी जायेगी। यह बात भी सही है कि जितनी आमदनी हमें होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है। आमदनी तथा खर्च में जो अन्तर है उसे सरकार बाजार ऋण तथा अन्य कर्जों से पूरा करती है। अगले वित्तीय वर्ष में इस मद में 4 हजार 5 सौ 46 करोड़ रुपये कर्ज लेने का अनुमान लगाया गया है।

60. अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हमारी सरकार इस बजट के माध्यम से कोई नया कर नहीं लगा रही है। इसके बावजूद भी राजस्व में योजना आयोग की अनुशंसा से अधिक वृद्धि करने की हमारी मंशा है।

61. अध्यक्ष महोदय, इस सदन की अनुमति से हमने वित्तीय वर्ष 2006-07 में मूल्य वर्द्धित कर प्रणाली लागू की है। जिस समय मूल्य वर्द्धित कर प्रणाली लागू करने पर इस सदन में चर्चा हो रही थी उस समय यह आशा की गयी थी कि इससे कर संग्रहण में वृद्धि होगी। VAT प्रणाली के परिणाम सामने अच्छे आ रहे हैं। फरवरी 2007 तक बिक्री कर में 18 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है।

62. अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2007-08 में राज्य सरकार का प्रस्तावित बजट 16 हजार 4 सौ 1 करोड़ रुपये है जिसमें गैर योजना मद में 8 हजार 8 सौ 61 करोड़ रुपये, राज्य योजना मद में 6 हजार 6 सौ 76 करोड़ रुपये, केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत 6 सौ 37 करोड़ रुपये तथा केन्द्रीय योजनागत योजना में 2 सौ 27 करोड़ रुपये रखने का प्रस्ताव है।

63. अध्यक्ष महोदय इस आय-व्ययक में गैर योजना मद में गत वर्ष के अनुमानित प्राक्कलन से मात्र 9.53 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

64. अध्यक्ष महोदय, आप जानते है कि राज्य सरकार को एक बड़ी राशि बिजली विपत्र के भुगतान हेतु झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को देनी है। आये दिन माननीय उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों में इस बात को लेकर मुकदमें हो रहे हैं। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि झारखण्ड राज्य में विद्युत विपत्रों के कारण सरकार पर जो बकाया है, उसका भुगतान एकमुश्त में कर दिया जाय। अनुमान लगाया गया है कि यह राशि 526 करोड़ रुपये होगी। गैर योजना मद में जो वृद्धि हुई है, उसमें यह राशि भी शामिल है। यदि राज्य विद्युत बोर्ड के बकाए को छोड़ दें तो गैर योजना मद में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 3.02 प्रतिशत की मामूली वृद्धि बनती है।

65. अध्यक्ष महोदय, गैर योजना मद में कर्णाकित राशि तथा राज्य योजना मद में कर्णाकित राशि को यदि सरसरी तौर पर देखा जाय तो अगले वित्तीय वर्ष के कुल बजट का 54 प्रतिशत गैर योजना मद में कर्णाकित है तथा 46 प्रतिशत योजना मद में उपबंधित है।

66. अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार विकास दर में उत्तरोतर वृद्धि की आशा रखती है। वित्तीय वर्ष 2005-06 में भारत सरकार के केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा झारखण्ड राज्य के लिए अनुमानित विकास दर 9.28 प्रतिशत (at current prices) आँकी गयी है। वित्तीय वर्ष 2007-08 के बजट में राज्य सरकार द्वारा 13.5 प्रतिशत (at current prices) की वृद्धि दर की आशा है।

67. अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार अपने संसाधनों को बढ़ाने तथा वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने का इरादा रखती है। सदस्य, राजस्व पर्षद की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गयी है जिसमें विशेषज्ञों के साथ-साथ राजस्व संग्रहण से संबंधित सभी विभागीय सचिवों को भी रखा गया है। यह समिति राज्य सरकार को नये संसाधन जुटाने के उपायों पर अपनी अनुशंसा देगी। सरकार कर-वंचना रोकने के भी कारगर कदमों को उठाने का विचार रखती है। कर संग्रहण को सुव्यवस्थित तथा पाददर्शिता से करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने विभिन्न राज्यों की सीमाओं से सटे नौ स्थानों पर इन्टीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाने का निर्णय लिया है। इस योजना में काम भी आगे बढ़ा है। धनबाद, जमशेदपुर, गुमला तथा गढ़वा में चेक पोस्ट का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। अन्य स्थानों पर भी कार्य शीघ्र शुरू करने का प्रयास है। इन सभी चेक पोस्टों के निर्माण से, ऐसा आकलन है कि इससे राजस्व दोगुना हो जायेगा।

68. अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उद्देश्य से वित्त विभाग के अंतर्गत Centre for Fiscal Studies के माध्यम से कर तथा संसाधन उगाही के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हुए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति के माध्यम से प्रशासी विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेश दिया जाता है ताकि किसी प्रकार के नये कर का प्रस्ताव नहीं करते हुए भी राज्य सरकार अधिक से अधिक राजस्व संग्रहण में सफल हो सके। इससे राज्य सरकार के सकल वित्तीय घाटे में भी कमी आयेगी।

69. अध्यक्ष महोदय, सरकार राजकोषीय उत्तरदायित्व विधेयक इसी सत्र में प्रस्तुत करने जा रही है। इस विधेयक के लागू होने से भी वित्तीय प्रबंधन में और अधिक पारदर्शिता तथा विभिन्न स्तरों (Levels) पर उत्तरदायित्व का निर्धारण हो सकेगा। निःसंदेह इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे। इस विधेयक के लागू हो जाने से जहाँ मूलधन के भुगतान करने में और अधिक समय मिल सकेगा वहीं, ब्याज दर में भी कमी आयेगी। जिसके फलस्वरुप राज्य की देनदारियों का भार कम होगा।

70. वित्तीय सुधार कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए राज्य के राजस्व घाटा को वित्तीय वर्ष 2006-07 में 713 करोड़ रुपये से घटाकर वित्तीय वर्ष 2007-08 में 507 करोड़ रुपये में सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है जो कि सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.84 प्रतिशत है।

71. वित्तीय सुधारों का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि राज्य के सकल वित्तीय घाटा को कम किया जाय। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार सकल वित्तीय घाटा को इस वित्तीय वर्ष में 5238 करोड़ रुपये से कम करते हुए वित्तीय वर्ष 2007-08 में 4775 करोड़ रुपये करना चाहती है। आशा है कि वित्तीय वर्ष 2007-08 के अंत तक सकल वित्तीय घाटा, सकल घरेलू उत्पाद का 7 प्रतिशत से भी नीचे आ जायेगा। हमारी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2007-08 के बजट को वृद्धि, विकास, कार्य कुशलता तथा सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निर्मित किया है।

72. अध्यक्ष महोदय, अंत में, मैं झारखण्ड को समृद्धि व पूर्ण रूप से विकसित राज्यों की कतार में लाने का पुनः संकल्प दोहरना चाहता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम झारखंडवासियों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य का विकास करने में सफल होंगे।

73. अध्यक्ष महोदय, हमारे संसाधन सीमित हैं, हमारे सामने अनेक बाधाएँ हैं, परन्तु हमारा संकल्प प्रचण्ड तूफान की तरह है, जो अपने वेग से सामने की बाधाओं को दूर उड़ा देगा।

'सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
देखना है जोर कितना बाजू-ए-कातिल में है।'

74. अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक को सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूँ। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए मैं तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।

-जोहार झारखण्ड

(यह बजट भाषण दिनांक 19 मार्च, 2007 को सभा में वित्त मंत्री द्वारा दिया गया।)

***